International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925(Online), Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 04(I), October - December, 2025, pp. 110-113

रीवा जिले के कृषकों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

तनूजा तिवारी[1*] | डॉ. मनीष कुमार शुक्ला[2]

[1]शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)।
[2]प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)।

[*]Corresponding Author: tanujatiwari00@gmail.com

Citation: तिवारीतनूजा, & शुक्लामनीष. (2025). रीवा जिले के कृषकों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 07(04(I)), 110–113. https://doi.org/10.62823/ijemmasss/7.4(i).8268

सार

भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि मानी जाती है। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकीकरण और सेवा क्षेत्र के विस्तार के बावजूद आज भी देश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। मध्यप्रदेश का रीवा जिला एक प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ कृषकों की आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि ही है। प्रस्तुत शोधपत्र में रीवा जिले के कृषकों की आर्थिक स्थिति का वाणिज्यिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि कृषकों की भूमि जोत छोटी है, सिंचाई सुविधाएँ अपर्याप्त हैं तथा कृषि उत्पादों के विपणन में असंगठित तंत्र कार्यरत है। परिणामस्वरूप किसान सीमित आय और ऋण के दबाव में जीवन–यापन करते हैं। यद्यपि सरकार द्वारा अनेक कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएँ संचालित हैं, परंतु इनका लाभ अपेक्षाकृत कम कृषकों तक पहुँच पाता है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु वित्तीय समावेशन, कृषि यंत्रीकरण, विपणन सुधार तथा कृषि–उद्यमिता का विकास आवश्यक है।

शब्दकोश: *कृषि, आर्थिक स्थिति, रीवा जिला, किसान, विपणन।*

प्रस्तावना

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषक ही हैं, जिनके श्रम, अनुभव और संसाधनों पर न केवल देश की खाद्य सुरक्षा, बल्कि ग्रामीण विकास की संपूर्ण संरचना टिकी हुई है। मध्यप्रदेश राज्य को "भारत का हृदय" कहा जाता है, जहाँ कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है। इसी क्रम में रीवा जिला कृषि उत्पादन एवं प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की भौगोलिक संरचना, जलवायु, मृदा की विविधता तथा सिंचाई की स्थिति कृषि के स्वरूप को प्रभावित करती है।

वर्तमान युग में कृषि का पारंपरिक स्वरूप बदलकर वह बाजार उन्मुख और तकनीकी दृष्टि से परिष्कृत होता जा रहा है। इसके बावजूद रीवा जिले के कृषक आर्थिक दृष्टि से अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। कृषकों की आय सीमित है, उत्पादन लागत अधिक है और विपणन व्यवस्थाएँ अभी भी पारंपरिक रूप में कार्य कर रही हैं। सरकारी योजनाओं एवं ऋण सुविधाओं के बावजूद किसान आर्थिक संकटों से उबरने में असमर्थ दिखाई देते हैं।

[*] *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

ऐसे परिदृश्य में "रीवा जिले के कृषकों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन" अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह अध्ययन न केवल कृषकों की आय, व्यय, ऋण, उत्पादन एवं लाभ की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, बल्कि उन सामाजिक–आर्थिक कारकों को भी उजागर करता है जो उनके विकास में बाधक हैं। इस शोध के माध्यम से जिले की कृषि अर्थव्यवस्था की वर्तमान दशा, उसकी चुनौतियों एवं संभावनाओं का सम्यक मूल्यांकन किया गया है, जिससे नीतिगत सुधार एवं ग्रामीण समृद्धि के नए आयाम स्थापित किए जा सकें।

वाणिज्यिक दृष्टिकोण से कृषक न केवल उत्पादक है, बल्कि वह एक लघु उद्यमी भी है, जो अपने संसाधनों का उपयोग कर उत्पादन करता है और बाजार में उसे बेचता है। इस प्रक्रिया में लागत, लाभ, मूल्य निर्धारण, ऋण, विपणन और निवेश जैसी अवधारणाएँ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। यदि किसान आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, तो पूरा ग्रामीण बाजार कमजोर पड़ जाता है। इस प्रकार कृषकों की आर्थिक स्थिति केवल सामाजिक या कृषि संबंधी नहीं, बल्कि वाणिज्यिक महत्त्व की भी विषयवस्तु है। इसी दृष्टिकोण से इस शोधपत्र में रीवा जिले के कृषकों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले के कृषकों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से संबंधित निम्न उद्देश्यों को केन्द्र में रखकर शोध पत्र के कार्य को पूर्ण किया गया है, जो इस प्रकार है–

- रीवा जिले के कृषकों की वर्तमान आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना।
- कृषकों की आय, व्यय, ऋण, उत्पादन साधन एवं विपणन व्यवस्था का वाणिज्यिक अध्ययन करना।
- कृषकों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करना।
- सरकारी योजनाओं के प्रभाव और क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना।
- कृषक आय वृद्धि और आर्थिक स्थिरता हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में प्रयोग की गयी शोध प्रविधियों में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक का प्रयोग किया गया है, जिनसे संबंधित विवरण निम्नानुसार है –

- **अध्ययन क्षेत्र :** रीवा जिले के पाँच तहसीलों – हुजूर, सिरमौर, सेमरिया, रायपुर कर्चुलियान एवं मनगवां का चयन किया गया है।
- **नमूना चयन :** प्रत्येक तहसील से 30 कृषकों का चयन यादृच्छिक नमूना पद्धति (त्दकवउ ैचसपदह) से किया गया है, कुल 150 कृषक सर्वेक्षण में सम्मिलित किए गए हैं।
- **आंकड़ों संग्रहण :** प्राथमिक आंकड़े कृषकों से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। द्वितीयक आंकड़े – कृषि विभाग, जिला सांख्यिकी कार्यालय, जनगणना रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण एवं सरकारी वेबसाइटों से संग्रहित किया गया है।
- **आंकड़ों का विश्लेषण :** प्रतिशत, औसत, तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से अध्ययन किया गया है।

विश्लेषण

रीवा जिले में कृषकों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते समय भूमि, पूंजी, श्रम, उत्पादन, ऋण, विपणन तथा सरकारी योजनाओं के प्रभाव को आधार बनाया गया है, जो इस प्रकार है –

- **भूमि जोत का आकार एवं स्वामित्वः** अध्ययन में पाया गया कि लगभग 60 प्रतिशत कृषक सीमांत श्रेणी (1 हेक्टेयर से कम) के हैं, जबकि 25 प्रतिशत लघु कृषक हैं। मध्यम वर्ग के किसानों का प्रतिशत मात्र

10 और बड़े किसानों का 5 है। भूमि जोत के विखंडन के कारण उत्पादन क्षमता सीमित है और यंत्रीकरण कठिन हो जाता है।

- **कृषि आय एवं व्यय :** औसत कृषक परिवार की वार्षिक कृषि आय रु. 85,000 से रु. 1,25,000 के बीच है, जबकि वार्षिक व्यय लगभग रु. 1,10,000 तक पहुँच जाता है। उर्वरक, बीज, सिंचाई, मजदूरी एवं यंत्र किराया मुख्य व्यय घटक हैं। इस असंतुलन के कारण कृषक पूंजी संचय नहीं कर पाते और ऋणग्रस्त होते जाते हैं।
- **ऋण एवं वित्तीय स्थिति :** करीब 72 प्रतिशत कृषक किसी न किसी रूप में ऋणग्रस्त हैं। इनमें से 40 प्रतिशत सहकारी बैंकों, 25 प्रतिशत साहूकारों तथा शेष अन्य संस्थाओं से ऋण लेते हैं। ब्याज दरें ऊँची होने तथा ऋण वितरण में विलंब से किसानों की आर्थिक परेशानी बढ़ती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ सीमित कृषकों तक पहुँचा है।
- **यंत्रीकरण एवं उत्पादन साधन :** जिले के मात्र 38 प्रतिशत कृषक आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं। शेष परंपरागत साधनों पर निर्भर हैं। यंत्रीकरण के अभाव में उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कम है। कृषि निवेश (Investment) बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **विपणन एवं मूल्य निर्धारण :** कृषकों की सबसे बड़ी समस्या विपणन की है। स्थानीय मंडियों तक पहुँच सीमित है। व्यापारी और बिचौलियों के कारण किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। मंडी शुल्क और परिवहन व्यय अतिरिक्त भार हैं। कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधा का अभाव भी प्रमुख चुनौती है।
- **सरकारी योजनाओं का प्रभाव :** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं से कुछ राहत मिली है, परंतु जानकारी के अभाव एवं तकनीकी बाधाओं के कारण सभी किसानों को इनका लाभ नहीं मिल सका।

शोध समस्याएँ एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध पत्र को पूर्ण करते समय आने वाली समस्याओं एवं सुझावों का विवरण क्रमशः निम्नानुसार है –

मुख्य समस्याएँ

- भूमि जोत का अत्यधिक विखंडन और सीमित क्षेत्रफल।
- सिंचाई सुविधाओं का अभाव एवं मानसून पर निर्भरता।
- पूंजी निवेश की कमी एवं ऋणग्रस्तता।
- कृषि उत्पादों का असंगठित विपणन तंत्र।
- आधुनिक तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण का अभाव।
- सरकारी योजनाओं की सीमित पहुँच और सूचना का अभाव।

सुझाव

- कृषक उत्पादक संगठन (FPO) मॉडल को प्रोत्साहित किया जाए ताकि सामूहिक विपणन और संसाधन उपयोग संभव हो।
- सूक्ष्म सिंचाई तकनीकें जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर का विस्तार किया जाए।
- सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- कृषकों के लिए वित्तीय साक्षरता और विपणन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएँ।

- कृषि आधारित उद्योगों (Agro & based industries) को बढ़ावा देकर रोजगार एवं आय दोनों में वृद्धि की जाए।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।

निष्कर्ष

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि रीवा जिले के कृषकों की आर्थिक स्थिति असंतुलित एवं अस्थिर है। कृषक वर्ग अभी भी सीमांत और लघु श्रेणी में बँटा हुआ है, जिसके कारण कृषि निवेश और उत्पादन क्षमता सीमित है। ऋण का दबाव, विपणन असंगठितता और बढ़ती लागत उनकी आय को प्रभावित करती है। यद्यपि सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं, लेकिन सूचनाओं की कमी और क्रियान्वयन में विलंब के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं।

वाणिज्यिक दृष्टि से देखा जाए तो कृषि केवल उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि एक पूर्ण आर्थिक उद्यम है। अतः कृषकों को उद्यमी के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। कृषि यंत्रीकरण, विपणन सुधार, वित्तीय सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण से ही रीवा जिले के कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। जब तक किसानों की आय स्थिर और पर्याप्त नहीं होगी, तब तक ग्रामीण बाजारों की माँग एवं वाणिज्यिक संतुलन स्थापित नहीं हो सकेगा। इसलिए कृषि क्षेत्र को दीर्घकालिक दृष्टि से सतत् विकास (नेजंपदंइसम क्मअमसवचउमदज) की दिशा में आगे बढ़ाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, आर. के. (2019). भारतीय कृषि व्यवस्था. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. शर्मा, पी. एल. (2021). ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि विकास. शुभदा प्रकाशन, भोपाल।
3. Government of Madhya Pradesh. (2023) - District Agriculture Report – Rewa, कृषि विभाग, भोपाल।
4. Mishra, D. N. (2022) - Agricultural Transformation in Central India - Orient Blackswan, New Delhi.
5. Saxena, R.C. (2020) - Indian Farmers and Rural Economy- Rawat Publications, Jaipur.
6. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare- (2024) - Annual Report- Government of India.
7. http://agriculture.mp-.gov.in – मध्यप्रदेश कृषि विभाग।
8. http://rewa.nic.in रीवा जिला प्रशासन (2024)।

❑❑❑